रिफायनरी के कच्चे माल से प्लास्टिक, फार्मा व ऑटोमोबाइल उत्पादों का निर्माण होगा- भजनलाल

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एचपीसीएल उद्योग विभाग व उद्योगों के बीच 18 त्रिपक्षीय समझौते हुए

जयपुर, 19 अप्रेल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बालोतरा स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयों को डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच 18 त्रिपक्षीय समझौते (एमओयू) हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रेल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन कर देश और प्रदेश को ऐतिहासिक सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) विकसित किया गया है। इससे उद्यमी सीधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसमें प्लास्टिक, फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के उत्पादों का निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में रविवार को बालोतरा स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच 18 त्रिपक्षीय समझौते हुए।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि रिफायनरी से निकलने वाले पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथीन (एचडीपीई/एलएलडीपीई) बेंजीन, टोलुइन और ब्यूटाडाइन जैसे उप-उत्पादों के आधार पर क्षेत्र में व्यापक सहायक उद्योग स्थापित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी के समीप बोरावास-कलावा में राजस्थान पेट्रो जोन (आरपीजेड) 1022 हैक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में लगभग 30 हैक्टेयर भूमि विकसित की जा चुकी है। वहीं, 86 औद्योगिक भूखण्डों में से 45 भूखण्डों का आवंटन भी किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान पेट्रो जोन के द्वितीय चरण में 213 हैक्टेयर में 257 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध होंगे, जिनके लिये ए कैटेगरी की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जोन का तृतीय चरण 780 हैक्टेयर में होगा, जिसमें से 447 हैक्टेयर के लिये कैटेगरी ए की पर्यावरण स्वीकृति लेने हेतु आवेदन किया जा चुका है। इसमें रामनगर (थोब), सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, बोरावास विस्तार और खेमाबाबा नगर में लगभग 780 हैक्टेयर भूमि का आवंटन रीको के पक्ष में किया गया है।

उल्लेखनीय है कि रिफाइनरी से मुख्य ईंधन के अतिरिक्त, भारी मात्रा में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल उत्पाद निकलेंगे, जो आगामी औद्योगिक इकाइयों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का कार्य करेंगे। पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथीन (एचडीपीई/एलएलडीपीई), बेंजीन, टोलुइन और ब्यूटाडाइन जैसे उप-उत्पादों के आधार पर क्षेत्र में व्यापक सहायक उद्योग स्थापित होंगे। इन कच्चे माल के प्रसंस्करण से घरेलू और औद्योगिक उपयोग के विविध उत्पाद, जैसे प्लास्टिक फर्नीचर, कृषि पाइप, पैकेजिंग फिल्म्स, ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड एवं बंपर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिकल सीरिंज और पेंट-डिटर्जेंट जैसे रसायनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होगा।

कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों के निरंतर विस्तार से रोजगार के अवसरों का व्यापक सृजन हुआ है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग शिखर अग्रवाल ने पचपदरा रिफाइनरी की विशेषताओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया। इस अवसर पर एचपीसीएल के मार्केटिंग डायरेक्टर अमित गर्ग और पेट्रो केमिकल हैड सौगाता चौधरी सहित, निवेशक एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

तृणमूल की रणनीतिकार आई-पैक ने काम बंद किया, कर्मचारियों को 11 मई तक छुट्टी पर भेजा

शनिवार रात आई-पैक ने कर्मचारियों को ई-मेल भेजकर सूचित किया कि कानूनी अड़चनों के कारण बंगाल में काम फिलहाल रोका गया है

- यह माना जा रहा है कि 23 और 29 अप्रैल के मतदान के दौरान आई-पैक की अनुपस्थिति तृणमूल के जमीनी चुनाव प्रबंधन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि तृणमूल ने कहा कि आई-पैक के काम रोकने की खबर निराधार है।

कोलकाता, 19 अप्रैल। बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में उस समय एक चर्चा तेज हो गई, जब तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही चुनावी रणनीतिकार संस्था आई-पैक के कामकाज को अस्थाई रूप से बंद करने की खबरें सामने आईं।

शनिवार देर रात आई-पैक के कर्मचारियों को कथित तौर पर भेजे गए ई-मेल में कानूनी बाध्यताओं का हवाला देते हुए 20 दिनों की छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष की एक सुनियोजित साजिश करार दिया है।

सूत्रों के अनुसार, साल्टलेक स्थित आई-पैक कार्यालय से कर्मचारियों को भेजे गए ई-मेल में कहा गया है कि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण बंगाल में कामकाज फिलहाल रोका जा रहा है। कर्मियों को 11 मई तक के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है।

रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में हाल ही में ईडी द्वारा आई-पैक के सह-संस्थापक व निदेशक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी और संस्था के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद यह कदम उठाया गया है। चर्चा यह भी है कि मतदान की महत्वपूर्ण तारीखों (23 और 29 अप्रैल) के दौरान आई-पैक की अनुपस्थिति तृणमूल के जमीनी चुनावी प्रबंधन को प्रभावित कर सकती है। इन खबरों के मीडिया में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की। पार्टी ने कहा कि आइ-पैक द्वारा काम रोकने की खबरें पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। आई-पैक की बंगाल टीम पूरी तरह सक्रिय है और हमारी चुनावी रणनीति योजनानुसार चल रही है।

आई-पैक और जांच एजेंसियों के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ज्ञात हो कि कुछ समय पहले ईडी की छापेमारी के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आइ-पैक दफ्तर पहुंची थीं और केन्द्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया था।

अब सवाल यह है कि क्या आई-पैक के कर्मी पर्दे के पीछे से काम करना जारी रखेंगे? सूत्रों का कहना है कि संस्था का एक हिस्सा वर्क फ्रॉम होम के जरिए सक्रिय रह सकता है, जबकि तृणमूल नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि उनके चुनाव प्रचार की गति कम नहीं होगी।

पूर्व केन्द्रीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

महत्वपूर्ण पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक अनुभवी नेता की नियुक्ति से कूटनीतिक संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है

एक्सप्रेस वे की दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए

- अदालत ने कहा, कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 2 प्रतिशत है। पर इन पर सड़क दुर्घटनाओं में 30 प्रतिशत मौत होती हैं।

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। देश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि एक्सप्रेसवे मौत के गलियारेनहीं बनने चाहिए और छोटी-छोटी लापरवाहियों की वजह से जान नहीं जानी चाहिए।

मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस जेके महेश्वरी और एएस चांदुरकर की बेंच ने बताया कि देश की कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 2 प्रतिशत हैं, लेकिन यहां करीब सड़क हादसों में 30 प्रतिशत मौतें होती हैं, जो बेहद चिंताजनक है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि, भारी या कमर्शियल वाहनों को सड़क या किनारे खड़ा करने पर रोक होगी, सिर्फ तय जगहों पर ही पार्किंग होगी। हाईवे के किनारे नए ढाबे, दुकान या कोई भी अवैध निर्माण तुरंत रोक दिए जाएंगे। 60 दिनों के अंदर ऐसे सभी अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया गया है। हर जिले में हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो सड़क सुरक्षा पर नजर रखेगी। हाईवे पर कैमरे, स्पीड मॉनिटर और इमरजेंसी सिस्टम (एटीएमएस) लगाए जाएंगे। पुलिस और प्रशासन को नियमित गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला 2025 में राजस्थान और तेलंगाना में हुए बड़े सड़क हादसों के बाद लिया गया, जिनमें कई लोगों की जान चली गई थी।

मांस, मछली, दवा, अचार नेपाल में लेकर नहीं आ सकते

नेपाल सरकार ने नये आर्थिक प्रतिबंध लगाए, भारतीय बाज़ार से सौ रूपये अधिक की खरीद पर कस्टम ड्यूटी लगाई

- दुकानदारों का कहना है कि नेपाल के लोग रोज़मर्रा का सामान खरीदने भारतीय बाज़ारों में आते थे। नये प्रतिबंधों का असर बाज़ार की रौनक तथा नेपाल की तराई में रहने वालों के जीवन पर पड़ने वाला है।

वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण), 19 अप्रैल। नेपाल सरकार के नए आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब भारत-नेपाल सीमा पर साफ दिखने लगा है। वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के 36 नंबर फाटक पर नेपाली प्रशासन की ओर से एक पोस्टर चस्पा कर कई वस्तुओं को भारत से नेपाल ले जाने पर रोक लगा दी गई है।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल द्वारा लगाए गए इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि डालडा, पेय पदार्थ, मांस, मछली, दवा, अचार, समेत कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भारत से खरीदकर नेपाल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही, सीमा पर तैनात नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स नागरिकों को इस नियम की जानकारी देते हुए सख्ती से पालन करा रही है।

स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि नेपाल सरकार के नए फैसले के अनुसार, सीमावर्ती इलाकों के लोग अब भारतीय बाजारों से 100 रुपये से अधिक की खरीदारी बिना शुल्क नहीं कर सकेंगे। तय सीमा से ज्यादा खरीदारी करने पर उन्हें कस्टम ड्यूटी देनी होगी।

इन नए नियमों का असर सीमावर्ती भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है। वाल्मीकिनगर और आसपास के बाजारों में नेपाली ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है।

स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पहले नेपाल के लोग रोजमर्रा के सामान की खरीदारी के लिए भारतीय बाजारों में आते थे, लेकिन अब सख्ती के कारण उनकी आवाजाही कम हो गई है। इससे बाजारों की रौनक फीकी पड़ गई है और व्यापारियों की आय पर असर पड़ रहा है।

नेपाल के इस फैसले का असर न केवल भारतीय बाजारों पर, बल्कि नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी पड़ने लगा है। जरूरी सामानों की उपलब्धता और खरीदारी दोनों, प्रभावित हो रही हैं।

इस बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसके बाद ही कॉलेज जाती थीं।

बाद के एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने और सहपाठियों के जीवन के बीच अंतर के बारे में बात की। जहां उनके सहपाठी नए और फैशनेबल कपड़ों से प्रभावित थे, वहीं बनर्जी केवल सादा कॉटन साड़ी खरीद सकती थीं। ये साड़ियाँ बाद में 'ब्रांड ममता' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं।

बनर्जी ने 1970 में स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज में दाखिला लिया। किशोरावस्था में ही उन्होंने कांग्रेस छात्र इकाई, छात्र परिषद, का नेतृत्व करते हुए कॉलेज चुनाव में जीत हासिल की।

कांग्रेस नेतृत्व ने उनके जोशीले राजनीतिक अंदाज को देखा और 1976 में उन्हें महिला कांग्रेस (इंदिरा) की बंगाल इकाई की महासचिव बना दिया।

1984 के लोकसभा चुनाव में, 29 साल की बनर्जी पहली बार संसद के लिए चुनी गईं। उन्होंने जादवपुर से दिवंगत सोमनाथ चटर्जी, वरिष्ठ वाम नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, को हराया।

1989 के चुनावों में हार के बाद, उन्होंने 1991 के चुनाव में कोलकाता साउथ सीट से जीत हासिल कर संसद में वापसी की। यह सीट 20 साल तक, उनके मुख्यमंत्री बनने तक, उनके पास ही रही।

सिविल मामलों में एफआईआर पर नये निर्देश जारी करें- हाई कोर्ट

- अदालत ने डीजीपी से कहा कि जाँच करें कि इस बारे में सर्कूलर की पालना क्यों नहीं हो रही।

जयपुर, 19 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने आपसी लेनदेन, जमीन जायदाद विवाद, वाणिज्यिक विवाद सहित, अन्य सिविल मामलों में एफआईआर दर्ज करने को गलत माना है। कोर्ट ने डीजीपी के सर्कुलर की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रकार के उल्लंखन की पुनरावृति रोकने के लिए नए सिरे से निर्देश जारी करें। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की बैंच ने यह निर्देश धर्मेन्द्र ठक्कर व अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि डीजीपी इस मामले में सर्कुलर की पालना नहीं होने के कारणों का पता लगाए और जिस अधिकारी द्वारा लापरवाही की गई है, उसकी पहचान करें। हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल नेचर के केस में एफआईआर तब तक दर्ज नहीं की जा सकती है, जब तक उसमें आपराधिक मामला नहीं बनता है। वहीं विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेना आवश्यक हैं। ऐसे में हम डीजीपी को निर्देश देते है कि वे अपने सर्कुलर की पूरे प्रदेश में कड़ाई से पालना करवाएं और इस प्रकार के उल्लंघनों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए नए निर्देश और जरूरी उपाय करने पर भी विचार करें।

दरअसल, इस मामले में टोंक जिले के निवाई थाना पुलिस ने दो पक्षों में कॉर्मिशियल विवाद को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। एक पक्ष ने आरोप लगाया था कि उसने दूसरे पक्ष को माल बेचा था, जिसके पेटे दूसरे पक्ष ने 18 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं किया। आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया कि यह पूरी तरह से सिविल नेचर का मामला हैं, लेकिन पुलिस इसे आपराधिक रंग देते हुए गिरफ्तारी का दवाब बना रही हैं।

ईरान ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यदि ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो उसके पुलों और बिजली संयंत्रों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसी बीच ईरान ने नाकाबंदी के चलते अपने वार्ताकारों को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पाकिस्तान जाएगा। हालांकि इस बार वार्ता का नेतृत्व कौन करेगा, इसपर संदेह है। जहां, खुद ट्रंप ने मीडिया से कहा कि इस बार उप राष्ट्रपति जेडी वेंस सुरक्षा कारणों से वहां नहीं जाएंगे और पश्चिम एशिया के लिए उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ वार्ता का नेतृत्व करेंगे, जबकि उनके दामाद जेरेड कुशनर टीम में शामिल रहेंगे। वहीं, वाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि वेंस पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी टीम को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।

अक्षय तृतीया पर गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुले

- गंगोत्री धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली पूजा प्रधानमंत्री के नाम से की।

देहरादून, 19 अप्रैल। उत्तराखंड के चार धामों में शामिल गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट रविवार को अक्षय तृतीया के पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इसके साथ ही उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा 2026 का श्रीगणेश हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री के नाम से की।

धार्मिक परंपराओं के अनुसार, रविवार को मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर से चलकर गंगोत्री धाम पहुंची। गंगोत्री धाम में विशेष पूजा-अभिषेक के साथ 12 बजकर 15 मिनट पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गये। इसी तरह मां यमुना की डोली भी शनिदेव महाराज की अगुवाई में शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से चलकर यमुनोत्री धाम पहुंची। धार्मिक विधि- विधान के साथ 12 बजकर 35 मिनट पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए।

गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शमिल हुए। धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से पहली विशेष पूजा-अर्चना की और देव डोली से आशीष भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक और सुदृढ़ व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। साथ ही, यात्रा मार्गों पर सुचारु यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मोदी ने सड़क ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जनसभा समाप्त करने के बाद वे अपने हेलीकॉप्टर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सड़क किनारे लगी एक झालमुड़ी की दुकान देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला रुका, मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। प्रधानमंत्री ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी इस पल की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में चार व्यस्त चुनावी रैलियों के बीच झाड़ग्राम में स्वादिष्ट झालमुड़ी का आनंद लिया। चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री का यह अंदाज अब राजनीतिक हलकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी व्यस्तता के बीच प्रधानमंत्री का आम लोगों के बीच पहुंचना उनके लिए सुखद अनुभव रहा।

तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में आग से 18 मजदूरों की मौत

- दोपहर में काम के दौरान पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद आग लगी। धमाकों की आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

विरुधुनगर, 19 अप्रैल। तमिलनाडु के जिला विरुधुनगर के कट्टनारपट्टी में रविवार दोपहर को एक पटाखा फैक्टरी में आग लगने से 18 मजदूरों की मौत होने की खबर है, लेकिन प्रशासन ने मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। इस हादसे में छह लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घटना में कई लोगों की मौत पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

पुलिस के अनुसार, कट्टनारपट्टी में दोपहर में मजदूरों के काम करने के दौरान एक पटाखा फैक्टरी में भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस व दमकलकर्मियों का दल मौके पर पहुंचा और बचाव व राहत कार्य शुरू किया। इस हादसे में वहां काम कर रहे 18 मजदूरों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कावेरी नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत

मैसूरु, 19 अप्रैल। कर्नाटक के मैसूरु जिले के केआर नगर क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कावेरी नदी में डूबने से छह लोगों की मौत हो गई। यह घटना अर्केश्वर मंदिर के पास स्थित पुराने एडथोरे अर्केश्वर स्वामी मंदिर क्षेत्र में हुई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है।

यहां स्थित हजरत खादर लिंगवल्ली दरगाह में उर्स कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार शामिल होने पहुंचे थे।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में भाजपा का प्रचार किया- ममता

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी तंत्र के दुरुपयोग व आचार संहिता के उल्लंघन की चुनाव आयोग को शिकायत करेंगी

- प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया कि जब महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में पास हो गया था तो अभी तक उसे लागू क्यों नहीं किया गया।

कोलकाता, 19 अप्रैल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने उन पर राजनीतिक अभियानों के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हुगली जिले के तारकेश्वर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए भाजपा के लिए प्रचार किया है।

ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी ने कल राजनीतिक अभियानों के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। हम इसकी निंदा करते हैं और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। टीएमसी प्रमुख ने पीएम पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी मढ़ा।

गौरतलब है कि शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक के बहाने कांग्रेस के साथ-साथ सभी विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। पीएम ने कहा था कि भारत की महिलाएं विपक्ष को भ्रूणहत्या के पाप के लिए कड़ी सजा देंगी।

वहीं, अब इसपर पलटवार करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री को भारत के लोगों को जवाब देना होगा कि वे अपनी पार्टी के लिए अवैध अभियान क्यों चला रहे हैं? दीदी ने सवाल किया कि जब महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में ही पास हो गया था, तो इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा-नीत सरकार ने जानबूझकर महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा में इतनी धृष्टता थी कि संख्या बल न होने के बावजूद, वे इसे लोकसभा में लाए। अब भाजपा का पतन शुरू हो गया है।

उत्साहित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक और नोटिस लाने पर विचार कर रही हैं। यह कदम उनके पिछले प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की ओर से खारिज किए जाने के कुछ ही दिनों बाद उठाया जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टियां इस मामले में चर्चा कर रही हैं। माना जा रहा कि एक संभावित मसौदा तैयार करने पर काम भी कर रही हैं।

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दबाव बनाने की ये विपक्ष की एक कोशिश भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव वाले राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर, वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े विवाद सामने आए। इससे पहले कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह के विवाद सामने आए थे। ऐसे में विपक्ष का नया प्रस्ताव लाने का विचार एक राजनीतिक कमेंट का प्रयास भी प्रतीत हो रहा।

प्रस्तावित परिसीमन का मकसद विपक्ष के वोट बैंक को कमज़ोर करना है- खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष ने तमिलनाडु की चुनाव सभाओं में सवाल किया कि भाजपा ने अब तक महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया

- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा का महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का कदम महिलाओं के लाभ के लिए नहीं, केवल राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया है।

चेन्नई, 19 अप्रैल। तमिलनाडु चुनाव के बीच महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केन्द्र में आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बताते हुए कहा कि महिलाओं को अधिकार देने में देरी क्यों हो रही है। कृष्णागिरी और होसुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण को सही तरीके से लागू करने के बजाय परिसीमन के साथ जोड़कर पेश कर रही है। उनका आरोप है कि यह बिल महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लाया गया था।

खड़गे ने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन का मकसद चुनावी क्षेत्रों को बदलकर विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर करना है। उन्होंने दावा किया कि इसे महिला आरक्षण के नाम पर पेश किया गया, जबकि असल में यह वोटों को बांटने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के हित में नहीं है।

खड़गे ने साफ कहा कि कांग्रेस महिलाओं, लोकतंत्र और समानता के पक्ष में है। उन्होंने एक-तिहाई महिला आरक्षण का समर्थन दोहराया और कहा कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्य के सांसदों की भी तारीफ की। खड़गे ने प्रधानमंत्री पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार, महंगाई और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर भी वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने नोटबंदी और अन्य फैसलों को भी असफल बताया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डीएमके, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तरह एकजुट हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे इस गठबंधन को समर्थन दें। खड़गे ने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र और समानता की रक्षा के लिए है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600